Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding Pradhan Mantri Awas Yojana in Maharashtra-laid.

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास का कार्य जो मोदी सरकार ने मिशन मोड पर लिया है यह अत्यंत सराहनीय है । उसके लिए मैं केन्द्र सरकार का सहृदय आभारी हूं । प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में अतथा ब वर्गवारी के लाभार्थियों को आवास का आबंटन हो चुका है । किन्तु जिनके नाम ड वर्गवारी में है उनको आवास की मान्यता के लिए रखी शर्तों की वजह से उनके खुद के आवास का सपना अधर में रह सकता है । समय की जरूरतों के अनुसार गरीब लोग मेहनत से कम दामों में किसी अन्य से टू-व्हिलर खरीदकर आजीविका के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, रोजाना मेहनत करक मासिक दस हजार रूपये तक आय कमा लेते है लेकिन आवास बनवाने में मेरे संसदीय जनजाति क्षेत्र में गरीबी के अन्य कारणों की वजह से 5 एकड़ वाला किसान भी आवास नहीं बना पाता ।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ड वर्गवारी लाभार्थियों हेतु कड़ी शर्तों को शिथिल कर उनके खुद के आवास के सपनों को साकार करें ।

इसके अलावा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्रों में जिन्हें आवास आबंटित हुए है उनके लिए केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को धन का आबंटन किया गया है किंतु महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लाभार्थियों को धन का आबंटन अभी तक नहीं किया है जिससे आवास पूर्णतः तैयार होने में दिक्कतें आ रही है । अतः उक्त संबंध में महाराष्ट्र सरकार को आवश्यक निर्देश देने की जरूरत है ।